ए.एफ.आर.

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

युगलपीठ; माननीय न्यायमूर्ति धीरेन्द्र मिश्रा, एवं

माननीय न्यायमूर्ति आर.एन. चन्द्रकार

रिट रिट याचिका क्रमांक.1528 /2006

यचिककर्तागण अरविन्द मिश्रा एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट रिट याचिका क्रमांक.4778 /2008

यचिककर्तागण एस.के. दुबे एवं एक अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट रिट याचिका क्रमांक.1519 /2008

यचिककर्तागण विजय तान्डेय व अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

रिट रिट याचिका क्रमांक.2724/2007

यचिककर्तागण डॉ. आर.के.गौराहा व अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

आदेश विचार्थ प्रस्तुत

-

हस्ता/
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायधीश

माननीय श्री आर.एन.चंद्राकर, न्यायमूर्ति

हस्ता/
आर.एन.चंद्राकर
न्यायधीश

मै सहमत हूँ.

आदेश की घोषणा हेतु 18 अगस्त 2009 को सूचीबद्ध करें.

हस्ता/
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

युगलपीठ; माननीय न्यायमूर्ति धीरेन्द्र मिश्रा, एवं

माननीय न्यायमूर्ति आर.एन. चन्द्रकार

रिट रिट याचिका क्रमांक.1528 /2006

यचिककर्तागण

1. अरविन्द मिश्रा,

   पिता-श्री दशरथ लाल मिश्रा,उम्र लगभग 40 वर्ष, व्यवसाय - व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेमेतरा, वर्तमान में पदस्त खंड शिक्षा अधिकारी, बेमेतरा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
2. अनिल कुमार तिवारी, पिता श्री भुवनेश्वर प्रसाद तिवारी, उम्र लगभग 40 वर्ष, व्यवसाय: व्याख्याता, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सरकंडा बिलासपुर (छ.ग.)
3. डी.के. जैन, पिता स्वर्गीय पी.आर. जैन, उम्र लगभग 43 वर्ष, व्यवसाय: व्याख्याता, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)
4. दिलीप केशरवानी, पिता श्री दयानंद गुप्ता, उम्र लगभग 45 वर्ष, व्यवसाय: व्याख्याता, वर्तमान में पदस्त सहायक परियोजना अधिकारी, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर (छ.ग.)
5. मोती चंद्र राय, पिता श्री जगदीश प्रसाद राय, उम्र लगभग 42 वर्ष, व्यवसाय: प्रधान पाठक, शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिलासपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(छ.ग.)

6. अनुपम सिंह, पिता श्री पी.एच. सिंह, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी: मधुबन रोड, बिलासपुर (छ.ग.)

7. कु. अनीता बारवे, पिता श्री एस.यू. बारवे, उम्र लगभग 34 वर्ष, व्यवसाय: उच्च श्रेणी शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कन्नेवाड़ा, बालोद, जिला दुर्ग (छ.ग.) में पदस्थ, निवासी: 21/बी, स्ट्रीट एमपीआर, सेक्टर II, ज़ोन 1 भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

8. संतोष कुमार मिश्रा, पिता श्री राधेश्याम मिश्रा, उम्र लगभग 39 वर्ष, व्यवसाय: सहायक शिक्षक (निम्न श्रेणी शिक्षक), शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)

9. गणेश दास कुर्रे, उम्र लगभग 37 वर्ष, पिता श्री बलिराम कुर्रे,शिक्षाकर्मी ग्रेड -1 शासकीय शिवलाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बेमेतरा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

10. पारस कुमार रात्रे, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता श्री जी.डी. रात्रे, शिक्षाकर्मी ग्रेड-II शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बैजलपुर, तहसील बेमेतरा, जिला- दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>विरुद्ध</u>

उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारा सचिव,

स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय,
डीकेएस भवन रायपुर (छ.ग.)

2. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय पेंशन बाड़ा, रायपुर (छ.ग.)
3. लोक सेवा आयोग सचिव द्वारा, शंकर नगर रोड, रायपुर (छ.ग.)

रिट रिट याचिका क्रमांक.4778/2008

यचिककर्तागण

1. एस.के. दुबे
पिता- श्री जे.पी. दुबे, उम्र लगभग 41 वर्ष,व्याख्याता शासकीय माध्यमिक उच्चतर विद्यालय, पाली, जिला- कोरबा (छ.ग.)
2. राजकुमार द्विवेदी, पिता- रामधन द्विवेदी, उम्र लगभग 41 वर्ष, उच्च श्रेणी शिक्षक छत्तीसगढ़ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिरकोना, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सचिव, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
3. परीक्षा नियंत्रक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
4. अवर सचिव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)

रिट रिट याचिका क्रमांक.1519 /2008

यचिककर्तागण

1. विजय तांडे, पिता श्री माखन लाल तांडे, उम्र लगभग 38 वर्ष, व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सेमरताल, जिला- बिलासपुर निवासी - देवनंदन नगर, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)
2. धनंजय पाण्डेय, पिता-श्री एन.के. पाण्डेय, उम्र लगभग 41 वर्ष, वर्तमान में प्रधान पाठक के रूप में पदस्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हरदीकला (टोना), जिला- बिलासपुर, निवासी - टिकरापारा, बिलासपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग डीकेएस भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग, रायपुर (छ.ग.)

रिट रिट याचिका क्रमांक.2724/2007

यचिककर्तागण

1. डॉ. आर.के. गौराहा, उम्र लगभग 40 वर्ष, पिता -श्री टी.पी. गौराहा, व्याख्याता शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

2. नरेंद्र कुमार कौशिक, उम्र लगभग 44 वर्ष, पिता श्री आर.एस. कौशिक, व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पांढी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
3. शिव कुमार गेंडले, उम्र लगभग 46 वर्ष, पिता श्री जी.डी. गेंडले, व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बेलतरा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
4. के.के. बंजारे, उम्र लगभग 40 वर्ष, पिता श्री एस.पी. बंजारे, प्रधान पाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, चांटीडीह, बिलासपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य
   द्वारा सचिव
   स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय, डीकेएस भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग
   द्वारा सचिव, राज्य लोक सेवा आयोग, शंकर नगर रोड, रायपुर (छ.ग.)

उपस्थित -

श्री प्रतीक शर्मा, रिट रिट याचिका क्रमांक. 1528/06 में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता।

श्री आनंद ददरिया, रिट रिट याचिका क्रमांक. 4778/08 और 1519/08 में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता।

श्री संजय के. अग्रवाल, रिट रिट याचिका क्रमांक. 2724/07 में याचिकाकर्ताओं की ओर से तथा रिट रिट याचिका क्रमांक. 1528/06 में हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता।

श्री किशोर भादुड़ी, सभी याचिकाओं में राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता।

श्री आशीष श्रीवास्तव, प्रतिवादी-छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से अधिवक्ता।

श्री राजीव श्रीवास्तव और श्री अली असगर, रिट रिट याचिका क्रमांक. 1528/06 और 4778/08 में हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता।

आदेश

(पारित दिनांक 18 अगस्त ,2009)

न्यायमूर्ति धीरेन्द्र मिश्रा द्वारा

01. यह याचिकाएँ इस सामान्य आदेश द्वारा निराकरण की जा रही हैं, क्योंकि इन याचिकाओं का विषय-छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग (संक्षेप में "पी.एस.सी.") द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर चयन के लिए दिनांक 19.1.2005 को प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 14.1.2005 के तहत शुरू कि गई चयन प्रक्रिया है .

02. रिट याचिका क्रमांक. 1528/06 में याचिकाकर्ता राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग में व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, उच्च श्रेणी शिक्षक, और निम्न श्रेणी शिक्षक हैं, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 9 और 10 क्रमशः शिक्षाकर्मी ग्रेड । और ॥ हैं। इसमें याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया को इस आधार पर चुनौती दी है कि चयन/पात्रता के मापदंड चयन प्रक्रिया के लंबित रहने के दौरान बदले नहीं जा सकते हैं; चयन हेतु विज्ञापन अस्पष्ट और भ्रामक था, और साथ ही छत्तीसगढ़ शैक्षिक सेवा (विद्यालय प्रभाग) भर्ती और पदोन्नति नियम, 1982 (संक्षेप में "नियम, 1982") और नियम, 1982 के नियम 8(2) के तहत बनाई गई अनुसूची-III के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जो स्नातकोत्तर डिग्री (न्यूनतम द्वितीय श्रेणी) बी.एड. या समकक्ष योग्यता के साथ "उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 5 वर्ष के शिक्षण अनुभव के रूप में योग्यता निर्धारित करता है ,और इस प्रकार यह मनमाना , भेदभावपूर्ण , अनुचित और संविधानिक के अनुच्छेद 14 के अधिकारातित है .

03. रिट याचिका क्रमांक. 4778/08 में याचिकाकर्ता राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग में व्याख्याता और उच्च श्रेणी शिक्षक हैं। उन्होंने प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (सुविधा के लिए संक्षेप में "प्राचार्य") के पद के लिए 14.1.2005 के विज्ञापन के अनुसरण में चयन प्रक्रिया में भाग लिया; लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की सूची में उनके नाम अनुलग्नक P/4 के अनुसार थे; और उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र जारी किए गए थे। माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका क्रमांक. 1380/06 में 27 नवंबर, 2006 को पारित आदेश के अनुसार पी.एस.सी. को कानून और आदेश में की गई टिप्पणियों के अनुसार सूची को फिर से बनाने

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

का निर्देश दिया था। हालांकि, पी.एस.सी. ने सूची को फिर से बनाते समय, संशोधित सूची में उन कई ऐसे उम्मीदवारों के नाम शामिल करके इसमें से याचिकाकर्ताओं के नाम हटा दिए विज्ञापन की आवश्यक पात्रता शर्तों को भी पूरा नहीं करते हैं। इस याचिका में, याचिकाकर्ताओं ने पी.एस.सी. द्वारा जारी 5.8.2008 के प्रेस नोट के साथ-साथ लिखित परीक्षा के संशोधित परिणाम और साक्षात्कार के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची को चुनौती दी है।

04. रिट याचिका क्रमांक.डब्लू पी.1519/08 और 2724/07 में याचिकाकर्ता स्कूल शिक्षा विभाग में व्याख्याता और प्रधानाध्यापक हैं। उन्होंने 19.1.2005 को जारी विज्ञापन के तहत शुरू की गई प्राचार्य के पद के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लिया। लिखित परीक्षा के बाद, 28.2.2006 को प्रकाशित परिणाम में सफल उम्मीदवारों की सूची में उनके नाम शामिल थे। उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक.डब्लू.पी.1380/ में 27.11.2006 को पारित आदेश में की गई टिप्पणियों के अनुसार पी.एस.सी. को विधि सम्मत चयन सूची को फिर से तैयार करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, आदेश पारित होने के एक वर्ष से अधिक समय बाद भी पी.एस.सी. ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में चयन सूची तैयार नहीं की है। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ताओं ने उत्तरवादिगण को याचिकाकर्ताओं का परिणाम तुरंत घोषित करने और चयन प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश देने की प्रार्थना की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

05. संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि पी.एस.सी. ने अपने 14.1.2005 के विज्ञापन के माध्यम से जो 19.1.2005 को समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था, राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य के कुल 46 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। पात्रता मापदंड विज्ञापन के खंड 4(ग) में दिए गए थे, जिसके अनुसार एक उम्मीदवार को न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ कला/वाणिज्य/विज्ञान में स्नातकोत्तर और बी.एड. या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए थी। इसमें आगे यह भी निर्धारित किया गया था कि उम्मीदवार को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उच्च श्रेणी शिक्षक/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। प्राचार्य के पद के लिए लिखित परीक्षा 8.1.2006 को आयोजित की गई थी और सफल उम्मीदवारों का परिणाम 28.2.2006 को घोषित किया गया था। सफल उम्मीदवारों को 28.3.2006 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। हालांकि, रिट याचिका क्रमांक.डब्लू पी.1380/06 में पारित अंतरिम आदेश के कारण, साक्षात्कार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित नहीं हो सका। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने 27.11.2006 के आदेश द्वारा रिट याचिका को अनुमति दी

और पी.एस.सी. को कानून और आदेश में की गई टिप्पणियों के अनुसार चयन सूची को फिर से तैयार करने का निर्देश दिया। हालांकि, चयन प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं हुई है।

06. याचिकाकर्ताओं ने नियम, 1982 के तहत शुरू की गई प्राचार्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया पर निम्नलिखित आधार पर प्रश्न उठाया है:

(i) कि नियम, 1982 के नियम 8(2) के तहत बनाई गई अनुसूची-III, जो "उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पांच वर्ष के शिक्षण अनुभव" को निर्धारित करती है, भेदभावपूर्ण, मनमाना और अनुक्तियुक्तकारण एवं संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार से परे है;

(ii) कि विज्ञापन के खंड 4(ग) में निर्धारित पात्रता मापदंड नियम, 1982 के तहत प्राचार्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित पात्रता मापदंड के अनुरूप नहीं है; चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता मापदंड बदल दिया गया है और चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद शिक्षाकर्मियों को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई है और उन्हें भी चुना गया है; और कि पी.एस.सी. द्वारा जारी किया गया भर्ती के लिए विज्ञापन अस्पष्ट और भ्रामक था, जिससे अन्य पात्र उम्मीदवारों/याचिकाकर्ताओं को चयन प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

07. श्री प्रतीक शर्मा, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि नियम, 1982 के नियम 8(2) के तहत बनाई गई अनुसूची-III में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पांच वर्ष के शिक्षण अनुभव को निर्धारित करना भेदभावपूर्ण, मनमाना और अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार से परे है, क्योंकि यह उन उम्मीदवारों के बीच भेदभाव करता है, जिनके पास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव है और अन्य, जिनके पास उनके नियोक्ता/राज्य सरकार द्वारा पदस्थापन के कारण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव नहीं हो सका। उपरोक्त पात्रता मापदंड मनमाना, भेदभावपूर्ण और अनुचित है क्योंकि उच्च योग्यता वाले व्याख्याता/उच्च श्रेणी शिक्षक, जिनके पास अपने नियोक्ता/राज्य द्वारा पदस्थापन के कारण अपेक्षित अनुभव नहीं है, उनके बिना किसी गलती के उनके साथ भेदभाव किया जाता है, और कम योग्य निम्न श्रेणी शिक्षक/सहायक शिक्षक और शिक्षाकर्मी ग्रेड-III, जिनके पास अपेक्षित अनुभव है, वे प्राचार्य के पद पर सीधी भर्ती में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

08. इस न्यायालय द्वारा रिट रिट याचिका क्रमांकमांक. 4150/2006 में डॉ. बी.पी. माथिल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य के मामले में 7.7.2009 को पारित आदेश पर अवलम्ब लिया गया है.

09. दुसरे आधार पर चयन प्रक्रिया के लिए विज्ञापन के खंड 4(ग) में निर्धारित पात्रता मापदंड नियम, 1982 के तहत प्राचार्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित पात्रता मापदंड के अनुरूप नहीं है,चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता मानदंड को बदल दिया गया है ,और शिक्षाकर्मियों कि परीक्षा में भाग लेने कि अनुमति दी गई है, और उनका चयन भी किया गया है, एवं पीएससी द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन अस्पष्टएवं भ्रामक था. जिससे पात्र उम्मीदवार याचिकाकर्ताओं परीक्षा में भाग लेने से वंचित हो गए. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उच्च श्रेणी शिक्षक/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष के शिक्षण अनुभव की शर्त नियम, 1982 के नियम 8(2) के तहत अनुसूची-III में निर्धारित पात्रता मापदंड से भिन्न है। उपरोक्त शर्त के कारण, याचिकाकर्ता संख्या 9 और 10, जो शिक्षाकर्मी हैं, चयन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सके, हालांकि, जब लिखित परीक्षा का परिणाम 28.2.2006 को घोषित किया गया और जब उन्होंने पाया कि उच्च श्रेणी शिक्षकों और व्याख्याताओं के साथ शिक्षाकर्मियों का भी चयन हुआ था, तब यह वर्तमान याचिका 24.3.2006 को दायर की गई थी। यह भी तर्क दिया गया था कि कला/वाणिज्य/विज्ञान में स्नातकोत्तर की आवश्यकता भी नियम, 1982 के विपरीत है, क्योंकि उक्त नियमों के अंग्रेजी संस्करण में केवल यही आवश्यकता निर्धारित है कि उम्मीदवार को द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उन्होंने आगे तर्क दिया कि 19.1.2005 को प्राचार्य के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाला विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद, पी.एस.सी. ने 24.2.2005 को राज्य को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षाकर्मियों के अनुभव को प्राचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए अनुभव के रूप में नहीं माना जा सकता है, और राज्य के 11.8.2005 के जवाब के आधार पर, पांच वर्ष के शिक्षण अनुभव वाले शिक्षाकर्मियों को पात्र माना गया। यह भी तर्क दिया गया कि उपर्युक्त स्पष्टीकरण के बाद विज्ञापन में शुद्धिपत्र प्रकाशित करके कोई नया आवेदन आमंत्रित नहीं किया गया था और जिन शिक्षाकर्मियों को लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी, उन्हें सफल घोषित कर दिया गया।

पी.एस.सी. ने 27.11.2006 को दिए गए अपने जवाब के कंडिका 10 में यह तर्क दिया है कि "केवल उच्च श्रेणी शिक्षक और व्याख्याता, जिनके पास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव है, वे नियुक्ति के लिए पात्र हैं"। हालांकि, रिट रिट याचिका क्रमांक. 4778/08 में विपरीत रुख अपनाया गया था। पी.एस.सी. ने 27.7.2009 को एक अतिरिक्त जवाब के माध्यम से अपने रुख में स्पष्ट विरोधाभास को सुलझाने की कोशिश की है, जिसमें यह कहा गया है कि 27.11.2006 के अपने जवाब के कंडिका 10 में उल्लिखित "केवल" शब्द एक अनजाने में हुई गलती थी।

यह स्थापित कानून है कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद मापदंड में बदलाव की अनुमति नहीं है। याचिकाकर्ता संख्या 9 और 10 और कई अन्य पात्र उम्मीदवार भर्ती के लिए पी.एस.सी. द्वारा जारी किए गए अस्पष्ट और भ्रामक विज्ञापन के कारण चयन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सके। 28.2.2006 को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद, जब उन्हें पता चला कि शिक्षाकर्मी, निम्न श्रेणी शिक्षक और निजी शिक्षक भी पात्र थे, तो पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करने के लिए यह वर्तमान याचिका दायर की गई थी।

10. श्री ए.के. ददरिया, रिट याचिका क्रमांक. 4778/08 में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया, लिखित परीक्षा में शामिल हुए और 28.2.2006 के परिणाम के अनुसार लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए। चयन नियम, 1982 के अनुरूप किया जाना था। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव उच्च श्रेणी शिक्षक/व्याख्याता के पद का होना चाहिए, इसलिए विज्ञापन के अनुसार शिक्षाकर्मी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे। हालांकि, 5.8.2008 के प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, पी.एस.सी. ने रिट याचिका क्रमांक. 1380/06 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कथित अनुपालन में साक्षात्कार के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की और जो व्यक्तियों, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं थे, उन्हें 28.2.2006 के परिणाम में सफल घोषित किए गए याचिकाकर्ताओं के नाम हटाकर चयन सूची में शामिल किया गया है।

रिट याचिका क्रमांक. 1528/06 में पी.एस.सी. द्वारा दायर किए गए जवाब का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया कि केवल आवश्यक अनुभव वाले व्याख्याता और उच्च श्रेणी शिक्षक ही प्राचार्य के पद के लिए आवेदन करने के पात्र थे। हालांकि, चयन सूची को पुनः तैयार करते

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

समय पी.एस.सी. द्वारा विपरीत रुख अपनाया गया है। जोरदार ढंग से यह तर्क दिया गया कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता मापदंड को बदला नहीं जा सकता है।

11. उत्तरवादी /राज्य ने अपने जवाब में 14.1.2005 के विज्ञापन के माध्यम से शुरू की गई चयन प्रक्रिया में किसी भी मनमानी से इनकार किया। उन्होंने याचिकाकर्ता संख्या 9 और 10 के संबंध में याचिकाकर्ताओं के अन्य अभिवचनों को भी अस्वीकार किया कि वे इस विज्ञापन से गुमराह हुए थे कि शिक्षाकर्मी पात्र नहीं हैं और तदनुसार, वे पद के लिए आवेदन नहीं कर सके। याचिकाएं विलंब और कमियों के आधार पर खारिज किए जाने योग्य हैं। याचिकाएं पोषणीय नहीं हैं क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं पी.एस.सी. द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लिया है और अब, उन्हें इस आधार पर चयन प्रक्रिया को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि पी.एस.सी. द्वारा निर्धारित पात्रता मापदंड खराब था।

12. पी.एस.सी. ने रिट याचिकाओं की पोषणीयता के संबंध में इसी तरह की आपत्तियां उठाई हैं। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं चयन प्रक्रिया में भाग लिया और 14.1.2005 के विज्ञापन में प्रकाशित पात्रता मापदंड के संबंध में पी.एस.सी. या राज्य के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। याचिकाएं केवल 28.2.2006 को परिणाम घोषित होने के बाद दायर की गई जब लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की सूची में याचिकाकर्ताओं के नाम नहीं थे। रिट याचिका क्रमांक. 1528/06 के याचिकाकर्ता संख्या 9 और 10 द्वारा पी.एस.सी. को पात्रता मापदंड के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था; उन्होंने पद के लिए आवेदन नहीं किया और विज्ञापन के प्रकाशन के लगभग एक वर्ष बाद नियम, 1982 के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। विज्ञापन के खंड 4(ग) से संलग्न नोट की प्रकृति शिक्षण अनुभव के संबंध में केवल स्पष्टीकरण की है और नियम, 1982 में निर्धारित योग्यता से कोई विचलन नहीं है। विज्ञापन के खंड 5 उप-खंड (8) का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया कि टीप केवल स्पष्टीकरण प्रकृति का था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शिक्षाकर्मियों की प्राचार्य के पद के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में, विज्ञापन के खंड 8 का हवाला देते हुए, यह प्रस्तुत किया गया था कि पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को अपनी उम्मीदवारी का निर्णय स्वयं करना था और यह स्पष्ट किया गया था कि केवल इसलिए कि उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है या उसे साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया है, वह उसे पात्र नहीं बनाएगा और उसकी

उम्मीदवारी किसी भी चरण में अस्वीकार की जा सकती है। नियम, 1982 का नियम 10 उम्मीदवारों की पात्रता/चयन के संबंध में पी.एस.सी. के निर्णय को अंतिम बनाता है।

13. हस्ताक्षेपकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव, ने भी इसी तरह के तर्क दिए हैं कि असफल उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में असफल रूप से भाग लेने के बाद उसे चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाएं चयन सूची में सफल उम्मीदवारों को पक्षकार के रूप में शामिल न करने के आधार पर खारिज किए जाने योग्य हैं, जिन पर इसका असर होने की संभावना है। यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाएं विलंब और कमियों से ग्रस्त हैं क्योंकि वे विज्ञापन जारी होने के लगभग एक वर्ष बाद, लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद ही दायर की गई थीं। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क उन मुद्दों पर हैं, जिन्हें रिट याचिकाओं में नहीं उठाया गया है, जिसकी इस संबंध में रिट याचिकाओं में किसी भी प्रक्काथनो के अभाव में कानून में स्वीकार नहीं है।

14. हस्ताक्षेपकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता ,श्री संजय के. अग्रवाल, अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि किसी अधिनियम और नियम की संवैधानिक वैधता को केवल इन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है: (i) कि यह भारत के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, (ii) कि यह संविधान के भाग-III में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में से किसी के प्रावधानों का उल्लंघन करता है; और (iii) .कि यह विधायी क्षमता से परे है या विधायी क्षमता की कमी है। वर्तमान मामले में, नियम, 1982 को संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाया गया है, यह 25 वर्ष की अवधि के लिए स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में 1984 से लागू है और 13.8.2008 से निरस्त कर दिया गया है और छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा राजपत्रित सेवा) भर्ती और पदोन्नति नियम, 2008 (संक्षेप में "नियम, 2008") द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। आक्षेपित नियम प्राचार्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए पात्रता मापदंड निर्धारित करता है और इसलिए, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम पांच वर्ष के शिक्षण अनुभव की योग्यता को मनमाना, भेदभावपूर्ण और अनुचित नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के साथ सीधा संबंध है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ताओं को केवल कठिनाई होना किसी वैध नियम को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है, जब तक कि यह न माना जाए कि यह भेदभाव या अनुचितता के दोष से ग्रस्त है और ऐसे मामलों में संविधान के अनुच्छेद 14 को आकर्षित नहीं किया जाता है। इस

तथ्यात्मक आधार के अभाव में कि उत्तरवादीगण ने पूर्वनिर्धारित योग्यता निर्धारित की है ताकि उन व्यक्तियों के अनुकूल हो, जिनके नाम प्राचार्य के पद की चयन सूची में शामिल हैं, नियम, 1982 बनाने में विधानमंडल के कि कोई भूमिका नहीं मानी जा सकती।

15. विभिन्न पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपने तर्कों के समर्थन में विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया है।

16. मामले के गुण-दोषों में प्रवेश करने से पहले, हम याचिकाकर्तागणों के अनुरक्षणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्तियों पर विचार करने का प्रस्ताव करते हैं।

17. उत्तरवादीगण ने याचिकाओं की पोषणीयता के संबंध में एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई है, इस आधार पर कि रिट याचिका क्रमांक. 1528/06 में याचिकाकर्ताओं ने बिना किसी आपत्ति के भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया है और इसलिए, उन्हें चयन मापदंड को चुनौती देने से वर्जित किया गया है। उन्हें चयन प्रक्रिया में भाग लिए बिना विज्ञापन और चयन प्रक्रिया को चुनौती देनी चाहिए थी। **धनंजय मलिक और अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य और अन्य**[1] के मामलों में दिए गए निर्णय का अवलंग लिया गया है.

18. यह सही है कि जिन याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया है और असफल घोषित किए गए हैं, उन्हें इस आधार पर चयन मापदंड को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता नियमों के विपरीत थी, जैसा कि धननंजय मलिक के मामले में माना गया है।

रिट याचिका क्रमांक. 1528/06 को 10 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किया गया था। पहले 8 याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया; 28.2.2006 को प्रकाशित सफल उम्मीदवारों की सूची में उनके नाम नहीं थे, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 9 और 10 ने इस अभिवचन के साथ याचिका दायर की है कि वे विज्ञापन के खंड 4(ग) में दी गई शर्त से गुमराह हुए थे, जिसमें विशेष रूप से निर्धारित किया गया था कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में केवल उन्हीं शिक्षकों को पात्र माना गया था, जिनके पास उच्च श्रेणी शिक्षक (संक्षेप में "यूडीटी") और व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव था, और इसलिए, वे पद के लिए आवेदन नहीं कर सके। श्री प्रतीक शर्मा द्वारा दिया गया तर्क यह है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 से 8 ने 24 मार्च, 2006 को उपर्युक्त याचिका केवल तभी दायर की, जब उन्हें पता चला कि शिक्षाकर्मियों को भी विज्ञापन के खंड 4(ग) में निर्धारित पात्रता मापदंड के विपरीत चयन प्रक्रिया में भाग

[1] (2008) 4 एससीसी 171

लेने की अनुमति दी गई थी और उन्हें भी 28.2.2006 के परिणाम में सफल घोषित किया गया था। रिट याचिका क्रमांक. 4778/08 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई है, जिनके नाम 28.2.2006 को प्रकाशित सफल उम्मीदवारों की सूची में थे। हालांकि, जब उन्होंने पाया कि 5.8.2008 को प्रेस विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित साक्षात्कार के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची में उनके रोल नंबर नहीं थे, तो उन्होंने इस आधार पर याचिका दायर की है कि पी.एस.सी. ने सफल उम्मीदवारों की सूची में उन शिक्षाकर्मियों को शामिल कर लिया है, जो विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं थे, और विज्ञापन के अनुसार पात्र और पहले के परिणाम में सफल घोषित किए गए याचिकाकर्ताओं के नाम हटा दिए हैं।

19. यह मानते हुए कि ये याचिकाएं केवल इस आधार पर दायर नहीं की गई हैं कि विज्ञापन में निर्धारित पात्रता मापदंड नियम, 1982 के अनुरूप नहीं है, बल्कि इस आधार पर भी कि पी.एस.सी. ने चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता मापदंड को बदल दिया है, हमारा मानना है कि इन याचिकाओं को केवल इस कारण से खारिज नहीं किया जा सकता है कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था और उन्होंने असफल होने के बाद ही याचिकाएं दायर कीं।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

20. प्रतिवादियों ने इन याचिकाओं को विलंब और कमियों के आधार पर और चयन सूची में सफल उम्मीदवारों को पक्षकार के रूप में शामिल न करने के आधार पर भी खारिज करने की प्रार्थना की है, जिन पर इसका असर होने की संभावना है। यह ध्यान में रखते हुए कि रिट याचिका क्रमांक. 1528/06 को दिनांक 24.3.2006 को सफल उम्मीदवारों की सूची 28.2.2006 को घोषित होने के तुरंत बाद दायर की गई थी, और यह भी ध्यान में रखते हुए कि रिट याचिका क्रमांक. 1380/27 का निराकरण दिनांक 27.11.2006 को उत्तरवादी को प्रतिवादियों को सफल उम्मीदवारों की सूची को फिर से तैयार करने के निर्देश के साथ नस्तिबद्ध की गई थी क्योंकि 28.2.2006 को घोषित सफल उम्मीदवारों की सूची राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार नहीं थी; और रिट याचिका क्रमांक. 4778/08 में 12.9.2008 को पारित आदेश के अनुसार, इस न्यायालय ने उत्तरवादिगण को साक्षात्कार आयोजित करने के बाद अंतिम परिणाम घोषित करने से रोक दिया था, हमारा मानना है कि इन याचिकाओं को विलंब और कमियों और चुने गए उम्मीदवारों को पक्षकार के रूप में शामिल न करने के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।

21. याचिकाकर्ताओं ने प्राचार्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए पात्रता मापदंड के रूप में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पांच वर्ष के शिक्षण अनुभव को निर्धारित करने वाले नियम, 1982 के नियम 8(2) के तहत बनाई गई अनुसूची-III की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती दी है कि यह भेदभावपूर्ण, मनमाना, अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकारातीत है।

22. **आंध्र प्रदेश राज्य सरकार और अन्य बनाम श्रीमती पी. लक्ष्मी देवी**[2] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47(ए) (एपी अधिनियम, 1998 की 8 द्वारा संशोधित के अनुसार) की संवैधानिक वैधता पर विचार करते हुए, विभिन्न भारतीय और विदेशी निर्णयों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद, यह निर्णय दिया कि किसी संविधि को असंवैधानिक घोषित करने से पहले, न्यायालय को यह सुनिश्चित होना चाहिए कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है। यदि दो विचार संभव हैं, एक संविधि को संवैधानिक बनाता है और दूसरा इसे असंवैधानिक बनाता है, तो पहले दृष्टिकोण को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही, न्यायालय को किसी कानून की संवैधानिक वैधता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, भले ही इसके लिए एक तनावपूर्ण व्याख्या या इसके दायरे को सीमित करने की आवश्यकता हो। न्यायालय का इससे कोई लेना देना नहीं है , कि उसकी राय में विधान बुद्धिमानीपूर्ण है या अविवेकपूर्ण। विधानमंडल को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में प्रयोग करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, बशर्ते कि यह अपनी संवैधानिक सीमाओं का स्पष्ट और जघन्य उल्लंघन न करे।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

23. **प्रफुल कुमार दास और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य**[3] के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका-45 में इस प्रकार टिपण्णी की है:

> "इस मामले में, याचिकाकर्ता उस लाभ की मांग कर रहे हैं जिसके वे अन्यथा हकदार नहीं हैं। हमारी राय में, विधायिका के पास एक उपयुक्त कानून पारित करने का आवश्यक क्षेत्राधिकार है जो अपने कर्मचारियों के साथ न्याय करेगा। यहां तक कि अन्यथा भी, उस प्रभाव के लिए एक उपधारणा निकाली जानी चाहिए। यदि अपेक्षित विधान मण्डल के कारण संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है, तो इस न्यायालय के लिए इसे केवल इस आधार पर अधिकार

[2] (2008) 2 एस.सी. 639

[3] (2003) 11 एससीसी 614

से परे घोषित करने की अनुमति नहीं होगी कि यह याचिकाकर्ताओं को कुछ कठिनाई का कारण बन सकता है। केवल कठिनाई किसी वैध कानून को रद्द करने का आधार नहीं हो सकती है जब तक कि इसे भेदभाव या अनुचितता के दोष से ग्रस्त नहीं माना जाता है। इस प्रकार, एक वैध कानून को केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अन्यथा अधिकारातीत पाया जाता है। हम नहीं मानते कि इस मामले में, संविधान का अनुच्छेद 14 आकर्षित होता है।"

24. **आर.एन. गोयल बनाम अश्विनी कुमार गुप्ता और अन्य**[4] के मामले में भी हरियाणा उद्योग (समूह अ) सेवा नियम, 1986 के नियम 9(1)(ख) की संवैधानिक वैधता पर इस आधार पर सवाल उठाया गया था कि यह अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता के तर्क को खारिज करते हुए, यह माना गया कि जहां संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियम, यदि वे सामान्य हित के लिए हैं, तो एक व्यक्ति को कठिनाई होती है, तो यह नियमों को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. बी.पी. माथिल के मामले के तथ्य, वर्तमान मामले के तथ्यों से अलग हैं, क्योंकि उद्धृत मामले में, याचिकाकर्ता ने संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए एक अतिरिक्त पात्रता मापदंड को शामिल करने को चुनौती दी थी। इसे याचिकाकर्ता के नुकसान के लिए सेवा की शर्त में एक एकतरफा बदलाव माना गया था और इसे मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 69 के तहत आवश्यक केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना शामिल किया गया था। उपरोक्त उद्धृत मामला इस आधार पर भी तथ्यों के आधार पर विभेदकारी बनाया गया था .उस मामले के याचिकाकर्ता के साथ केवल घटनास्थल इकाई में उसकी पदस्थापना के कारण पदोन्नति के मामलों में भेदभाव किया जा रहा था और यह ऐसा मामला नहीं था जहां नियमों के तहत सीधी भर्ती की जानी थी।

हालांकि, वर्तमान मामले में, नियम, 1982 के नियम 8(2) के तहत अनुसूची-III में निर्धारित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पांच वर्ष के शिक्षण अनुभव को केवल इस आधार पर मनमाना, भेदभावपूर्ण और अनुचित नहीं माना जा सकता है कि इससे याचिकाकर्ताओं को कठिनाई हो सकती है।

[4] (2004) 11 एस.सी.सी. 753

26. अब दूसरे आधार पर आते हैं, विज्ञापन का खंड 4(ग) इस प्रकार है:

"4. पद विवरण –

क) Xxxx xxxxx xxxxx

ख) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

ग) *अर्हताएं (आवश्यक)- कला/वाणिज्य/ विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा बी.एड. अथवा उसके समक्ष अर्हता एवं उच्चतर माध्यमिक शाला मे 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव.*

टिप- उच्चतर माध्यमिक शाला में 5 वर्ष का अनुभव उ.श्रे.शि. शिक्षक/व्याख्याता के पद को होना चाहिए."

विज्ञापन के खंड 4(ग) के अनुसार, अनिवार्य पात्रता न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ कला/वाणिज्य/विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि और बी.एड. या समकक्ष योग्यता और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव निर्धारित की गई है। एक नोट जोड़ा गया है कि पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव उच्च श्रेणी शिक्षक (संक्षेप में "यूडीटी") / व्याख्याता के पद का होना चाहिए, जबकि प्राचार्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए पात्रता मापदंड नियम, 1982 के नियम 8(2) के तहत बनाई गई अनुसूची-III द्वारा शासित है, जो यह निर्धारित करता है कि उम्मीदवार को न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर और बी.एड. या इसके समकक्ष योग्यता के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। नियम, 1982 के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों में स्नातकोत्तर की उपाधि के संबंध में अंतर है। अंग्रेजी संस्करण न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर निर्धारित करता है, जबकि हिंदी संस्करण न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ कला/वाणिज्य/विज्ञान में स्नातकोत्तर निर्धारित करता है, और बाकी की शर्तें नियम, 1982 के दोनों संस्करणों के तहत समान हैं। विज्ञापन में कला/वाणिज्य/विज्ञान में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी कि स्नातकोत्तर डिग्री निर्धारित करता है, जो पात्रता के लिए नियमों के हिंदी संस्करण के अनुरूप है।

उत्तरवादिगण द्वारा यह तर्क दिया गया है कि छत्तीसगढ़ राजभाषा अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, सभी विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, नियमों और विनियमों में उपयोग की जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी को निर्धारित किया गया है, और इसलिए, नियमों का हिंदी पाठ प्रमाणित होगा और हिंदी नियमों का अंग्रेजी अनुवाद मूल पर अधिभावी नहीं कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. **सत्यभान सिंह जादोन बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य**[5] के मामले में दिए गए निर्णय पर अवलंग लिया गया है।

28. यहां तक कि यदि हम यह मानते हैं कि विज्ञापन हिंदी में अधिसूचित नियम, 1982 के अनुसार जारी किया गया था, तो विज्ञापन में खंड 4(ग) की यह शर्त कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव उच्च श्रेणी शिक्षक (संक्षेप में "यूडीटी") / व्याख्याता के पद का होना चाहिए, हिंदी में अधिसूचित नियम, 1982 के नियम 8(2) के तहत बनाई गई अनुसूची-III में निर्धारित पात्रता मापदंड से विचलन है। यह स्थापित कानून है कि नियमों में उल्लिखित पात्रता की आवश्यकता का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। भर्ती करते समय, नियमों के तहत निर्धारित पात्रता मापदंड में अतिरिक्त योग्यता नहीं जोड़ी जा सकती है क्योंकि सरकार वैधानिक नियमों में संशोधन या उन्हें अधिक्रमित नहीं कर सकती है और भर्ती केवल नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए। हम अपने इस विचार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पी.के. रामचंद्र अय्यर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य**[6], **संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य**[7] और **मलिक मजार सुल्तान और अन्य बनाम यू.पी. लोक सेवा आयोग और अन्य**[8] के मामलों में निर्धारित कानून के सिद्धांतों से पुष्ट हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. इसके अलावा, पी.एस.सी. ने विज्ञापन में विशेष रूप से निर्धारित किया था कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव उच्च श्रेणी शिक्षक और व्याख्याता के पद का होना चाहिए, जबकि राज्य सरकार से प्राप्त बाद के स्पष्टीकरण के आधार पर, शिक्षाकर्मियों के आवेदनों पर भी विचार किया गया और उन्हें चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई और लिखित परीक्षा के परिणाम में सफल घोषित किया गया।

30. **मदन मोहन शर्मा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य**[9] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार सरकार के परिपत्र के आधार पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद, चयन प्रक्रिया के दौरान पात्रता मापदंड में बदलाव की स्वीकार्य नहीं है। चयन प्रक्रिया विज्ञापन के अनुसार जारी रहनी चाहिए।

पीएससी और हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से जोरदार ढंग से यह तर्क दिया गया कि विज्ञापन के खंड 5 के उप-खंड (8) ने शिक्षाकर्मियों के रूप में पांच वर्ष के अनुभव वाले इच्छुक प्रतिभागियों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी कि वे भी चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र

[5] 1997(2) एम.पी.यू. 487
[6] ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 54।
[7] ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 1910
[8] (2006)9 एस.सी.सी. 507
[9] ए.आई.आर. 2008 एस.सी. 1657

थे; विज्ञापन के खंड 4(ग) में संलग्न नोट केवल स्पष्टीकरण प्रकृति का था। यह भी तर्क दिया गया कि शिक्षाकर्मियों के अंक उपरोक्त विज्ञापन के जवाब में लागू हुए और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता मापदंड को बदल दिया गया था।

हमने खंड 5 के उप-खंड (8) की सावधानीपूर्वक जांच की है, जो केवल सामान्य प्रशासन विभाग के एक परिपत्र को संदर्भित करता है, जिसके अनुसार शिक्षाकर्मी सरकारी सेवाओं में ऊपरी आयु सीमा में उन वर्षों के लिए छूट के हकदार हैं, जिसके लिए उन्होंने शिक्षाकर्मियों के रूप में सेवा की है, और अधिकतम छूट 45 वर्ष की आयु तक है। यह कहीं भी यह निर्धारित नहीं करता है कि शिक्षाकर्मियों के रूप में पांच वर्ष के शिक्षण अनुभव वाले उम्मीदवार भी विज्ञापित पद के लिए आवेदन करने के हकदार हैं। अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों से, यह स्पष्ट रूप से प्रकट है कि पी.एस.सी. शिक्षाकर्मियों के रूप में अनुभव के संबंध में पात्रता मापदंड के बारे में निश्चित नहीं था और इसलिए, विज्ञापन के प्रकाशन के बाद राज्य सरकार से एक स्पष्टीकरण मांगा गया था और उसके बाद ही, 28.2.2006 को सफल उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. हम याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों में बल पाते हैं कि विज्ञापन के खंड 4(ग) में शर्त के कारण, रिट याचिका क्रमांक. 1528/06 के याचिकाकर्ता संख्या 9 और 10 और इसी प्रकार भी स्थिति वाले अन्य उम्मीदवार गुमराह हुए और वे चयन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सके।

32. उपरोक्त विवेचन के आधार पर, हमारी यह राय है कि पीएससी द्वारा प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन दिनांक 14.1.2005 (समाचार पत्र में 19.1.2005 को प्रकाशित) के धारा प्रारंभ की गई चयन प्रक्रिया नियम, 1982 के अनुरूप नहीं थी, क्योंकि विज्ञापन के खंड 4 (ग) में निर्धारित पात्रता मापदंड नियम, 1982 के अनुरूप नहीं था; पीएससी ने विज्ञापन के प्रकाशन के बाद विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मापदंड को बदल दिया और शिक्षाकर्मियों तथा अन्य उम्मीदवारों को, जो अन्यथा विज्ञापन के खंड 4 (ग) में निर्धारित शर्तों के अनुसार पात्र नहीं थे, चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी और उन्हें सफल भी घोषित किया, जो कानून में अनुमेय नहीं है। तदनुसार, हम मानते हैं कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में यूडीटी/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष के शिक्षण अनुभव की अतिरिक्त योग्यता के कारण, रिट रिट याचिका क्रमांकमांक 1528/06 में याचिकाकर्ता क्रमांक 9 और 10 सहित अन्य उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने से रोका गया।

33. फलस्वरूप, रिट रिट याचिका क्रमांक.1528/06 स्वीकार किया जाता है। विज्ञापन दिनांकित 14.1.2005/19.1.2005 के अनुसरण में प्रधानाचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद के लिए संपूर्ण चयन कार्यवाही एतद्वारा अभिखंडित किया जाता है।

34. परिणामत:, रिट याचिका(सेवा) क्र.4778/08, 1519/08 एवं 2724/07 को निराकृत किया जाता है।

35. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

हस्ता/
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायधीश

हस्ता/
आर.एन.चंद्राकर
न्यायधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

-Translated By Nasreen Khan

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur